उत्तर प्रदेश

विशिष्ट करेंट अफेयर्स

दिसंबर 2022

उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किया 33 हज़ार 700 करोड़ का अनुपूरक बजट

· 5 दिसंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरीकरण, औद्योगीकरण और धार्मिक विरासत स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिये 33,769 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया।

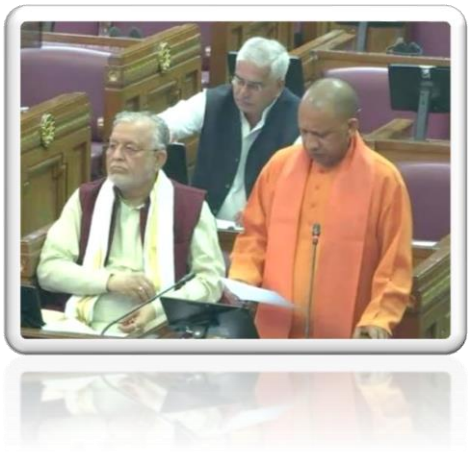

· उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया।

· 33,769 करोड़ रुपए के कॉर्पस में से 14,000 करोड़ रुपए नई योजनाओं के लिये आवंटित किये गए हैं। अगले वर्ष फरवरी में होने वाले उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन के लिये 56 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है।

· पूरक बजट में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिये कॉर्पस के साथ, सरकार ने कहा कि इसका लक्ष्य राज्य में 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। इसके लिये, सरकार का मार्गदर्शन करने के लिये नियुक्त परामर्श एजेंसी को 35 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है।

· राज्य सरकार ने इस बजट में 'नए शहरों' के बुनियादी ढाँचे और समग्र विकास के लिये 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

· पर्यटन, इलेक्ट्रिक वाहन, सौर ऊर्जा, स्टार्टअप और औद्योगिक पार्कों की स्थापना जैसे क्षेत्रों के लिये घोषित नई नीतियों के तहत दिये गए प्रोत्साहनों के लिये भी धन आवंटित किया जाएगा।

· औद्योगिक पार्क स्थापित करने में निवेश करने वाले निवेशकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये 300 करोड़ रुपए का कोष आवंटित किया जाएगा, जबकि 100 करोड़ रुपए स्टार्टअप की स्थापना से जुड़े प्रोत्साहन के लिये रखा गया है।

· पूरक बजट में स्मार्ट सिटी मिशन के लिये 899 करोड़ रुपए तथा नई सौर नीति 2022 के तहत सौर शहर स्थापित करने की सरकार की योजना के अनुरूप अयोध्या सौर शहर के विकास के लिये 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

· अपने पूरक बजट में, सरकार ने नई घोषित इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत सब्सिडी के लिये 100 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं, जबकि 1,000 नई बसों की खरीद के लिये 200 करोड़ रुपए, राज्य में ईको टूरिज्म विकसित करने के लिये 20 करोड़ रुपए और कुकरैल नाइट सफारी विकसित करने के लिये एक करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

· बजट में उत्तर प्रदेश में विभिन्न औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को ऋण देने के लिये 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, बिजली क्षेत्र में परियोजनाओं और योजनाओं के वित्तपोषण के लिये 5,900 करोड़ रुपए अलग रखे जाएंगे।

· उत्तर प्रदेश के चार शहरों- वाराणसी, नोएडा, आगरा और लखनऊ में अगले साल जी-20 लीडरशिप समिट के कार्यक्रमों की मेजबानी की जानी है, इन आयोजनों के लिये पूरक बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सूचना एवं संचार सेवाओं के विकास के लिये बजट में 804 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

· प्रदेश में सड़कों के निर्माण एवं रैंपिंग के लिये 2337 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, गन्ना विकास परिषद द्वारा निर्मित सड़कों के विकास के लिये 155 करोड़ रुपए अलग रखे जाएंगे। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के तहत स्टेडियम और ओपन जिम बनाने और विकसित करने के लिये 15 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं।

· पूरक बजट में कृषि ऋण सब्सिडी के लिये 190 करोड़ रुपए का प्रावधान भी है।

· आध्यात्मिक पर्यटन के लिये अपने प्रयास को जारी रखते हुए, सरकार ने नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र में सड़कों और सुविधाओं के विकास जैसे धार्मिक आकर्षण के आसपास के स्थानों को विकसित करने के लिये 5 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है।

उत्तर प्रदेश में बनेंगे एकीकृत न्यायालय परिसर

· 6 दिसंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार गुजरात के बड़ौदा में बने एकीकृत न्यायालय परिसर की तर्ज पर राज्य के दस ज़िलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एकीकृत न्यायालय परिसर का निर्माण किया जाएगा। विधानसभा से पास अनुपूरक बजट के माध्यम से इस विशेष परियोजना के लिये 400 करोड़ रुपए दिये गए हैं।

· एकीकृत न्यायालय परिसर के लिये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राज्य के जिन 10 ज़िलों का चयन किया है, वे हैं- महोबा, हाथरस, चंदौली, शामली, अमेठी, हापुड़, ऑरैया, सोनभद्र, संभल और चित्रकूट।

· मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्यों में अपराधों की अलग-अलग प्रकृति के अनुसार त्वरित न्याय के लिये अलग-अलग कानूनों से जुड़े अदालतों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। बहुत से जगहों पर किराये के भवनों में अदालतों के चलते न्यायिक अधिकारियों और फरियादियों दोनों को ही दिक्कत होती है। सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था में भी दिक्कतें आती हैं। इसको देखते हुए अदालतों के लिये एकीकृत कोर्ट परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

· इसके अलावा एक आदेश में उच्चतम न्यायालय द्वारा भी ऐसे न्यायालय परिसरों के निर्माण का आदेश दिया गया है।

· राज्य में मुख्यमंत्री के निर्देश पर लोक निर्माण, गृह तथा विधि एवं न्याय विभाग इस परियोजना पर काम कर रहे हैं। एकीकृत भवन में कोर्ट, जजों के चैंबर, मीटिंग हॉल, विडियो कोर्ट, पॉर्किंग, कैंटीन सहित सभी सुविधाओं के लिये जगह होगी।

· राज्य में 10 ज़िलों में बनने जा रहे इस एकीकृत अदालत परिसर में ज़िला और अधीनस्थ न्यायालय, वाणिज्यिक न्यायालय, विविध, ट्रिब्यूनल, फास्ट ट्रैक कोर्ट और लोक अदालत आदि होंगें। यहाँ न्यायालय भवन, अधिवक्ता चैंबर, सभागार के अलावा न्यायधीशों और न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये आवासीय कॉलोनी, पार्किंग और फूड प्लाजा भी होगा।

उत्तर प्रदेश के 6 ज़िलों में मेडिकल कॉलेज खोलने के टेंडर जारी

· 8 दिसंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि राज्य में 'एक ज़िला, एक मेडिकल कॉलेज' के तहत 6 ज़िलों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलने के लिये टेंडर जारी किया गया है।

· टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से राज्य के महोबा, मैनपुरी, बागपत, हमीरपुर, हाथरस और कासगंज में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिये निवेशकों को चयनित किया जाएगा।

· विदित है कि केंद्र सरकार की वायबलिटी गैप फंडिंग स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश के इन 6 ज़िलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हुई है।

· चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव ने बताया कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलने के लिये टेंडर जारी किया है। टेंडर का डिटेल जेम पोर्टल पर भी अपलोड कर दिया गया है।

· उन्होंने बताया कि 6 ज़िलों में मेडिकल कॉलेज खोलने में करीब 1525 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसमें से केंद्र सरकार सब्सिडी के रूप में करीब 1012 करोड़ रुपए का भार उठाएगी। एक कॉलेज को औसतन 160 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी।

· राज्य के महाराजगंज और शामली में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिये निवेशकर्त्ता का चयन का कार्य शुरू हो गया हैं। अगले साल तक महाराजगंज में उपचार शुरू होने की संभावना है। इसके अलावा शामली और मऊ में मेडिकल कॉलेज प्रक्रियाधीन है।

· प्रमुख सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आम लोगों को बेहतर और सुलभ चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में यह बड़ा कदम है। केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने से राज्य के धन की बचत होगी।

· उन्होंने बताया कि राज्य ज़िला अस्पताल और भूमि 33 साल की लीज पर देगी। इसके बाद निवेशकर्त्ता मेडिकल कॉलेज सरकार को वापस कर देगा। यह राज्य की संपत्ति होगी और साथ ही स्टांप ड्यूटी में छूट और उपकरण सब्सिडी भी देगी।

‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ की तर्ज पर ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन वेटलैंड’ की तैयारी

· 9 दिसंबर, 2022 को प्रदेश के पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन एवं जंतु उद्यान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अरुण कुमार सक्सेना ने जानकारी दी कि सरकार ने प्रदेश में 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट' की तर्ज पर अब 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन वेटलैंड' पर काम करने का फैसला किया है। इस संबंध में प्रदेश के सभी प्रभागीय वनाधिकारियों को प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गए हैं।

· राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अरुण कुमार सक्सेना ने बताया कि इस योजना के तहत हर जनपद में एक वेटलैंड को सँवारने का काम किया जाएगा, जिससे वह पर्यटन के लिहाज से आकर्षण का केंद्र बन सके।

· प्रदेश सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक जनपद में एक वेटलैंड को इको टूरिज्म के तहत विकसित किया जाए, जिससे पर्यटन के मानचित्र में इस वेटलैंड को खास स्थान मिल सके। इससे प्रदेश के इको टूरिज्म का दायरा और व्यापक होगा। सरकार की इस पहल से अभी तक जो वेटलेंड उपेक्षित स्थिति में हैं या जिन पर किसी का ध्यान नहीं गया है, उनका कायाकल्प हो सकेगा।

· इसके साथ ही राजधानी लखनऊ के कुकरैल में प्राणि उद्यान को शिफ्ट करने और नाइट सफारी का काम जल्द शुरू होगा। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 के अंत तक कुकरैल जू एवं नाइट सफारी की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है और लखनऊ चिड़ियाघर का अगला स्थापना दिवस कुकरैल में मनाए जाने का निर्णय किया गया है।

· वन मंत्री ने वन ट्रिलियन इकॉनामी के संबंध में वन विभाग को दिये गए दस हज़ार करोड़ के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये प्रदेश में लकड़ी आधारित उद्योगों की स्थापना के लिये जनपदवार लक्ष्यों को निर्धारण करने के निर्देश दिये। साथ ही काष्ठ कला बोर्ड की स्थापना के संबंध में चर्चा की गई।

· उन्होंने बरेली में जू स्थापना के प्रगति की जानकारी ली। वहीं सांडी नवाबगंज समसपुर पक्षीविहार, सारनाथ डियर पार्क, इंदिरा गांधी वनस्पति उद्यान, रायबरेली के बेहतर प्रबंधन के लिये सोसायटी-ट्रस्ट के गठन का प्रस्ताव जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में भी खुलेंगे जेनेरिक आधार के स्टोर

· 18 दिसंबर, 2022 को जेनेरिक आधार के संचालक अर्जुन देशपांडे ने बताया कि जेनेरिक आधार के मेडिकल स्टोर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में भी खोले जाएंगे। ग्रामीण इलाकों तक जेनेरिक दवाएँ पहुँचाने के लिये जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार और जेनेरिक आधार के बीच एमओयू होगा।

· गौरतलब है कि जेनेरिक आधार के संचालक अर्जुन देशपांडे ने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और बताया कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जेनेरिक आधार के ज़रिये मरीज़ों को सस्ती दर पर दवाएँ दी जा सकेंगी।

· उन्होंने बताया कि जेनेरिक आधार के करीब 1800 स्टोर चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में 150 स्टोर हैं। मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद इसे बढ़ाकर अब 700 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। जहाँ यह जेनेरिक स्टोर होगा, उससे करीब पाँच सौ मीटर दूर ही दूसरा स्टोर खोला जाएगा।

· उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जेनेरिक आधार के मेडिकल स्टोर चल रहे हैं। मरीज़ों को सस्ती दर पर दवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।

उत्तर प्रदेश में 5 हज़ार एकड़ में बनेगी नॉलेज स्मार्ट सिटी

· 18 दिसंबर, 2022 को सैन फ्राँसिस्को में आस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने नॉलेज स्मार्ट सिटी के लिये एमओयू साइन किया।

· सैन फ्राँसिस्को में यूएस बेस्ड सलोनी हार्ट फाउंडेशन ने राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और औद्योगिक विकास आयुक्त अरविंद कुमार की मौजूदगी में एमओयू साइन किया। वहीं आस्टिन यूनिवर्सिटी ने उत्तर प्रदेश में नॉलेज स्मार्ट सिटी के लिये 35 हज़ार करोड़ रुपए के निवेश का एमओयू साइन किया।

· यह नॉलेज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पाँच हज़ार एकड़ ज़मीन पर बनाया जाएगा, इसमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों का समावेश होगा।

· गौरतलब है कि राज्य की योगी सरकार ने राजधानी लखनऊ में 10-12 फरवरी के मध्य होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के ज़रिये 10 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों और अधिकारियों की 8 टीमों को 18 देशों में रोड शो और ट्रेड शो के ज़रिये निवेश आकर्षित करने के लिये भेजा है।

· इससे पहले स्वीडन बिज़नेस कम्युनिटी ने उत्तर प्रदेश में गहरी दिलचस्पी दिखाते हुए कुल 15000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। प्रदेश में निवेश आने से अलग-अलग क्षेत्रों में तो विकास होगा ही, साथ ही रोज़गार भी बढ़ेगा।

· उत्तर प्रदेश में निवेश करने वाली ये कंपनियाँ यहाँ फिल्म सिटी, रिटेल, टूरिज्म, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में पैसा लगाने के लिये तैयार हैं। स्वीडन के अलावा कनाडा के वैंकूवर से भी टीम योगी को 1200 करोड़ रुपए के छह एमओयू (MOU) प्राप्त हुए हैं।

· स्टॉकहोम में रोड शो के दौरान आयोजित विभिन्न बी2जी और जी2जी बैठकों में रक्षा, कपड़ा और वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा सहित अन्य क्षेत्रों में निवेश को लेकर चर्चा की गई।

वाराणसी में बनेगा 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' मॉल

· 20 दिसंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश उद्योग के संयुक्त आयुक्त उमेश कुमार सिंह ने बताया कि राज्य के वाराणसी के चांदपुर औद्योगिक संस्थान में चार मंजिला ओडीओपी (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडेक्ट) मॉल निर्माण का प्लान तैयार करने के निर्देश दिये गए हैं।

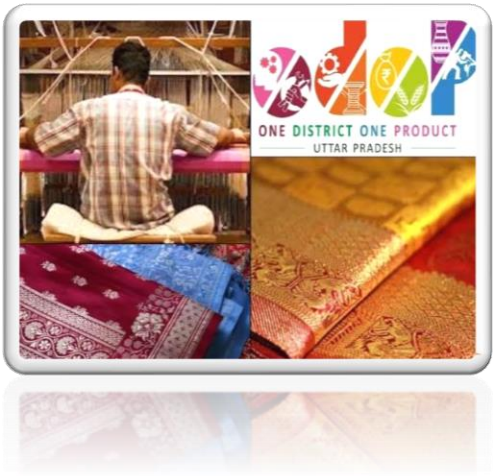

· उल्लेखनीय है कि वाराणसी के चांदपुर औद्योगिक संस्थान में करीब दो एकड़ क्षेत्र में फैले पार्क में ओडीओपी मॉल प्रस्तावित है। इस पार्क में पहले उद्योगों के लिये कोयला स्टोरेज होता था और यहाँ फ्लैटेड फैक्ट्री बनाने की भी योजना बनी थी।

· ओडीओपी मॉल के शहर में होने की वजह से यहाँ ट्रांसपोर्ट की बेहतर सुविधा मिलेगी। इससे बुनकरों, शिल्पियों को माल भाड़ा में राहत मिलेगी।

· उमेश कुमार सिंह ने बताया कि उद्योग विभाग ओडीओपी मॉल में बुनकरों, शिल्पियों और निर्यातकों को लीज पर जगह देगा। एकमुश्त रकम देकर बुनकर व शिल्पी वहाँ लंबे समय तक रह सकेंगे। इससे किराया आदि के खर्च में बार-बार फेरबदल के झंझट से निजात मिलेगी।

· ओडीओपी मॉल के निर्माण से सिल्क उत्पादों, मीनाकारी और लकड़ी के खिलौनों के कारोबार को प्रोत्साहन मिलेगा। मॉल का सबसे ज्यादा लाभ वाराणसी के चौक क्षेत्र के साड़ी व्यावसायियों को मिलेगा।

देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनेंगी मिर्जापुर की सानिया मिर्ज़ा

· 22 दिसंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर ज़िले के छोटे से गाँव की रहने वाली सानिया मिर्जा ने एनडीए की परीक्षा में 149वीं रैंक के साथ फ्लाइंग विंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। एनडीए से पास आउट होकर सानिया देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बन सकती हैं।

· गौरतलब है कि अबकी बार फ्लाइंग विंग में दो ही सीट हैं। एनडीए में मात्र 19 पद महिलाओं के लिये आरक्षित हैं। सब कुछ ठीक रहा तो एनडीए से पास आउट होकर सानिया को देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा।

· ज्ञातव्य है कि सानिया मिर्जापुर देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के छोटे से गाँव जसोवर की रहने वाली हैं। प्राइमरी से लेकर 10वीं तक की शिक्षा गाँव के ही पंडित चिंतामणि दुबे इंटर कॉलेज से पूरी की। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में ज़िला टॉपर भी रही हैं। इसके बाद सानिया ने शहर के गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज से 12वीं की पढ़ाई पूरी की।

· सानिया ने बीते 10 अप्रैल को एनडीए की परीक्षा दी। नवंबर में जारी लिस्ट में उनका चयन हुआ है। वे फ्लाइंग में चुनी जाने वाली दो महिलाओं में से एक हैं। वह एनडीए ट्रेनिंग के लिये 27 दिसंबर को पुणे में ज्वाइन करेंगी।

336 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा काशी इंटर मॉडल स्टेशन

· 25 दिसंबर, 2022 को उत्तर रेलवे मंडल के मंडल रेल प्रबंधक सुरेश कुमार सपरा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी के काशी रेलवे स्टेशन को मेजर अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के लिये टेंडर जारी किया गया है। करीब 336 करोड़ रुपए की इस परियोजना से काशी इंटर मॉडल स्टेशन बन जाएगा।

· सुरेश कुमार सपरा ने बताया कि इस परियोजना से काशी इंटर मॉडल स्टेशन बनने के साथ-साथ यहाँ यार्ड रीमॉडलिंग, कॉम्प्लेक्स और होटल निर्माण समेत कई कार्य किये जाएंगे। यहाँ टेक्नो फिजिबिलिटी सर्वे का काम पहले ही पूरा हो गया है। अगले साल दिसंबर तक डीपीआर का काम भी हो जाएगा।

· इस परियोजना के पहले और दूसरे प्रवेश द्वार को जोड़ते हुए कॉनकोर्स (सिटी सेंटर) भी बनाने का उद्देश्य है। काशी स्टेशन में रोज़ाना करीब 10 जोड़ी ट्रेनें रुकती हैं। इस कायाकल्प से स्टेशन की छवि पूरे तरीके से बदल जाएगी तथा इस रेलवे स्टेशन का कायाकल्प करने में ढाई साल का समय लग जाएगा।

· उन्होंने बताया कि इसके अलावा कैंट स्टेशन पर चार्ज़िंग सेंटर का टेंडर जारी होने से वाराणसी कैंट स्टेशन पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा मिलेगी। यहाँ जनवरी से इलेक्ट्रिक ह्वीकल चार्ज़िंग फैसिलिटी पॉइंट बनना शुरू हो जाएगा। मार्च तक यहाँ इलेक्ट्रिक दोपहिया और ई-रिक्शा समेत सभी छोटे-बड़े वाहनों को चार्ज करने की सुविधा मिलने लगेगी।

· ई-वाहनों को चार्ज करने के लिये फिलहाल वाराणसी में सरकारी या गैर-सरकारी स्तर पर कोई सुविधा नहीं है। मिर्ज़ामुराद में बना चार्ज़िंग स्टेशन सिर्फ ई-बसों के लिये ही है। ऐसे में कैंट स्टेशन पर बनने वाला ई-ह्वीकल चार्ज़िंग फैसिलिटी पॉइंट ऐसे वाहनों के लिये फायदेमंद साबित होगा।

पहली बार ईको टूरिज़्म थीम पर आयोजित होगा गोरखपुर महोत्सव

· 27 दिसंबर, 2022 को उक्तर प्रदेश के गोरखपुर के डीएफओ विकास यादव ने बताया कि प्रदेश में लोगों को जंगल और पर्यावरण की अहमियत समझाने के लिये वन विभाग पहली बार ईको टूरिज़्म की थीम पर गोरखपुर महोत्सव का आयोजन करेगा। यह महोत्सव 11 से 13 जनवरी, 2023 तक आयोजित किया जाएगा।

· डीएफओ विकास यादव ने बताया कि जंगल मैराथन के तहत पाँच किलोमीटर तक बच्चों व सामाजिक संगठनों, सामान्य नागरिकों को जंगल के बीच घुमाया जाएगा। इस दौरान लोगों को जंगल और उसके माहौल के बारे में जानकारी दी जाएगी। यह मैराथन देवरिया बाईपास के सूबा बाज़ार से शुरू होकर विनोद वन में खत्म होगा।

· उन्होंने बताया कि गोरखपुर महोत्सव में मैराथन, फोटो प्रदर्शनी, सिनेमा और स्टाल के माध्यम से लोगों को वन की खासियत और प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताया व समझाया जाएगा। इसमें वन विभाग की कार्ययोजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी।

· इसके अलावा ग्रीन ऑस्कर से सम्मानित विश्व विख्यात पर्यावरणविद् माइक एच. पांडेय द्वारा निर्देशित पाँच अलग-अलग फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में फिल्म के माध्यम से लोगों को ईको टूरिज़्म की खासियत को समझाने की कोशिश की जाएगी।

· वन विभाग और बैंबू मिशन की ओर से तैयार बाँस के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। कार्यक्रम स्थल पर ईको टूरिज़्म फोटोग्राफी का भी स्टाल लगाया जाएगा। इसमें शहर के अलग-अलग सुंदर प्राकृतिक स्थलों की तस्वीरें होंगी।

· चिड़ियाघर में दो दिन कार्यक्रम होंगे। एक दिन नेचर वॉक होगा और दूसरे दिन चिड़ियाघर के वेटलैंड में बर्डवाच कार्यक्रम होगा। अभी तक पाँच स्कूलों के बच्चों को कार्यक्रमों से जोड़ा गया है।

· ज्ञातव्य है कि ईको टूरिज़्म का मतलब है- प्राकृतिक सौंदर्य के करीब जाना और उसका आनंद लेना। इसके तहत पर्यटकों को प्राकृतिक क्षेत्रों में ले जाया जाता है, ताकि के कुदरत के सौंदर्य का आनंद ले सकें। साथ ही पर्यावरण के संरक्षण के बारे में जागरूक हो सकें।

अब चौरीचौरा नाम से जाना जाएगा गोरखपुर का मुंडेरा बाज़ार नगर पंचायत

· 27 दिसंबर, 2022 को गोरखपुर के एसडीएम शिवम सिंह ने बताया कि गोरखपुर के मुंडेरा बाज़ार नगर पंचायत का नाम जल्द ही चौरीचौरा हो जाएगा। शासन के प्रस्ताव पर निर्णय लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नाम परिवर्तन को लेकर अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी कर दिया है।

· एसडीएम शिवम सिंह ने बताया कि जंग-ए-आजादी के इतिहास में चौरीचौरा का नाम अमिट है। अंग्रेजी हुकूमत की ज्यादतियों के खिलाफ चौरीचौरा में हुए प्रतिशोध के शताब्दी वर्ष के दौरान ही इस ऐतिहासिक स्थल से जुड़े तथ्यों को दुरुस्त करने का अभियान शुरू किया गया है।

· उन्होंने बताया कि तहसील और थाने का नाम तो पहले से ही चौरीचौरा है। पहले विधानसभा क्षेत्र का नाम मुंडेरा बाजार था। वर्ष 2012 के चुनाव से पहले इस विधानसभा क्षेत्र का नाम भी चौरीचौरा कर दिया गया। मुख्य बाजार मुंडेरा बाजार होने के कारण नगर पंचायत का नाम अभी तक मुंडेरा बाजार ही रह गया।

· गौरतलब है कि तत्कालीन डीएम के. विजयेंद्र पांडियन ने मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नाम बदलकर चौरीचौरा नगर पंचायत करने के लिये शासन को प्रस्ताव भेजा था। प्रशासन के प्रस्ताव पर शासन ने गृह मंत्रालय को एनओसी के लिये प्रस्ताव भेज दिया था।

· एसडीएम शिवम सिंह ने बताया कि मुंडेरा बाजार एक बाजार है जो चौरीचौरा में समाहित है। पहले सिर्फ मुंडेरा बाजार के मतदाता थे और कुल 11 वार्ड थे। चुनाव से पूर्व विस्तारित क्षेत्र में भोपा बाजार, राघोपुर, चौरा, भगवानपुर, बाल बुजुर्ग गाँव भी सम्मिलित होने से अब 16 वार्ड और कुल मतदाताओं की संख्या 26 हज़ार हो गई है।

साबरमती की तर्ज पर अयोध्या में बसेगी ग्रीनफील्ड टाउनशिप

· 29 दिसंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार गुजरात के साबरमती की तर्ज पर अयोध्या में ग्रीन फील्ड टाउनशिप बसाने जा रही है। यह योजना 1438 एकड़ क्षेत्रफल में लाई जाएगी।

· इस योजना के लिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष राज्य आवास विकास परिषद ने इसका प्रस्तुतीकरण किया। इस दौरान गुजरात के वास्तुविदों को भी बुलाया गया था। उन्होंने साबरमती ग्रीन फील्ड के बारे में जानकारी दी।

· इसके आधार पर आवास विकास परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अयोध्या में ग्रीन फील्ड टाउनशिप का आकार ऐसा तैयार किया जाए जो पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हो। इसके लिये ज़रूरत के आधार पर वास्तुविदों को भी जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के आधार पर आवास विकास परिषद ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं।

· अयोध्या में ग्रीन फील्ड टाउनशिप की इस योजना को पहले चरण में 583 एकड़ क्षेत्रफल में बसाने की योजना है। पहले चरण के लिये 487 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया जा चुका है।

· दूसरे और तीसरे चरण में 855 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके अलावा टाउनशिप के आसपास व्यवसायिक क्षेत्र और पार्कों का इंतजाम किया जाएगा, जिससे लोगों को ज़रूरत के आधार पर सुविधाएँ मिल सके।

· विदित है कि वैदिक सिटी की परियोजना का मानक अहमदाबाद गिफ्ट सिटी के आधार पर तय होगा। नव्य अयोध्या परियोजना के अंतर्गत हाइवे के किनारे स्थित गाँवसभा शाहनवाजपुर एवं मांझा बरहटा में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड टाउनशिप योजना (वैदिक सिटी) में कई तरह के बदलाव भी किये जा रहे है और इसके लिये स्टैंडर्ड मानक भी निर्धारित किया जा रहा है।

हिन्दी संस्थान के 46वें स्थापना दिवस पर 70 साहित्यकार सम्मानित

• 30 दिसंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान का 46वाँ स्थापना दिवस समारोह आयोजित हुआ। इसमें वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. राम कठिन सिंह, कथाकार डॉ. सुधाकर अदीब व संस्थान के निदेशक आरपी सिंह ने सभी श्रेणियों के कुल 70 साहित्यकारों को सम्मानित किया।

• 26 वर्षों के अनवरत् लेखन से रचित महाकाव्य विधा की पुस्तक 'अथर्वा, मैं वही वन हूँ' के लिये भोपाल के आनंद कुमार सिंह को 'तुलसी पुरस्कार'दिया गया। कविता संग्रह 'राम धरा पर पुन: पधारो'के लिये शंकर सिंह को श्रीधर पाठक पुरस्कार से नवाजा गया। नाटक विधा की रचना 'कालपुरुष क्रांतिकारी वीर सावरकर'के लिए गाजियाबाद के साहित्यकार जयवर्धन जेपी को भारतेंदु हरिश्चन्द नामित पुरस्कार मिला।।

• यात्रा वृत्तांत विधा में पुस्तक 'सपनों का शहर सैन फ्रांसिस्को'के लिए नोएडा की साहित्यकार जयश्री पुरवार को अज्ञेय नामित पुरस्कार मिला। उपन्यास विधा में 'कंथा' पुस्तक के लिये वाराणसी के साहित्यकार श्याम बिहारी श्यामल को प्रेमचंद पुरस्कार दिया गया।

• बाल साहित्य विधा की पुस्तक 'मां कह एक कहानी'के लिये गाज़ियाबाद की साहित्यकार श्रद्धा पांडेय को सूर पुरस्कार से नवाजा गया। इतिहास विधा की पुस्तक 'सियासत का सबक'के लेखक यूपी के पूर्व डीजीपी और भाजपा सांसद बृजलाल को आचार्य नरेंद्र देव पुरस्कार मिला।

• पत्रकारिता विधा की पुस्तक ‘क्रोनोलॉजी इन कोविडटून्स’के लिये लखनऊ के पत्रकार हरिमोहन वाजपेयी ‘माधव’को धर्मवीर भारती सर्जना पुरस्कार से नवाजा गया। कहानी संग्रह विधा की पुस्तक ‘अनुभव के बोल’के लिये लखनऊ के रामजी भाई को यशपाल पुरस्कार मिला। इसमें 51 कहानियों का संग्रह है।